

भारत में डीएफआईडी के कार्यों का सारांश

2011-15

सितंबर 2011

हम भारत में क्यों कार्य करते हैं

भारत ब्रिटेन का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार और राष्ट्रकुल में सर्वाधिक आबादी वाला देश है। प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ब्रिटेन एवं भारत के बीच साझेदारी के नवीकरण और उसे गहन बनाने पर सहमत हुए हैं।

भारत तेजी से विकास कर रहा है और गरीबी से निपटने में अच्छी प्रगति कर रहा है। इसके बावजूद प्रतिदिन 1.25 डालर (80 पेन्स) से कम आय कमाने वाले विश्व के एक-तिहाई लोग भारत में रहते हैं और उनकी औसत आय चीन की तुलना में एक-तिहाई है। मध्य प्रदेश में आधे से भी अधिक बच्चे अल्प-पोषित हैं। बिहार में प्रत्येक चार व्यक्तियों में से सिर्फ एक व्यक्ति शौचालय की सुविधा का उपयोग कर पाता है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) की पूर्ति की वैश्विक सफलता में इन राज्यों में गरीबी में कमी लाना अत्यंत महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। समावेशी संवृद्धि एवं विकास भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम गरीबी घटाने में साझेदारी के साथ कार्य करते हुए स्वयं उसकी सफल योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे।



नवजात शिशु का सुरक्षित आगमन: मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की स्वास्थ्य कार्यकर्ता रेखा रावत गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में ले जाने और सुरक्षित प्रसव कराने में मदद करती हैं। रेखा बताती हैं— “इन सेवाओं के उपयोग के लिए महिलाओं को राजी करना मुश्किल कार्य है। लेकिन, मुझे तब विशेष संतुष्टि मिलती है, जब मैं उन्हें (इन सेवाओं को पाने के लिए) राजी कर लेती हूँ और वे अपने लिए लाभ महसूस करती हैं।”



हम अपनी विकास साझेदारी के कार्य को अधुनातन बनाते रहे हैं। हम अपने कार्यक्रम का फोकस बदलकर भारत के अति-गरीब राज्यों पर केंद्रित कर रहे हैं। हम नौकरियां, उत्पाद, ढांचागत सुविधाएं और बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने के सिलसिले में निजी सेक्टर की क्षमता के संवर्द्धन में मदद करना चाहते हैं। हमारी सहायता का उद्देश्य अति-गरीब महिलाओं एवं लड़कियों पर भी केंद्रित होगा, जिससे गुणवत्तायुक्त स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, पोषण और नौकरियां पाने में उनकी मदद की जा सके। इस दौरान हम आर्थिक सहायता-आधारित संबंध से महत्वपूर्ण वैश्विक मसलों के बारे में एक पारस्परिक, दोतरफा साझेदारी की ओर बढ़ना चाहते हैं, जिनमें व्यापार, वैश्विक विकास, जलवायु परिवर्तन एवं खाद्य सुरक्षा भी शामिल हैं।

स्कूल तक सफर: भारत में लड़कों की तरह ही अनेक लड़कियां निम्न प्राथमिक विद्यालय में पढ़ना चाहती हैं। पर, जब गरीबी परिवारों को यह चुनने के लिए मजबूर करती है कि कौन माध्यमिक विद्यालय में जाएगा तो आम तौर पर लड़कों को चुना जाता है। डीएफआईडी अगले चार सालों के दौरान वंचित वर्गों की युवतियों, खासकर दलित एवं आदिवासी लड़कियों को सेकन्डरी स्कूल की शिक्षा पाने में मदद करेगा। हम अधिक स्थानीय सेकन्डरी स्कूलों के निर्माण, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने और लड़कियों द्वारा स्कूल तक जाने के सफर का खर्च सीधे उन्हें प्रदान करने में मदद करेंगे।

हम क्या-क्या उपलब्धियां हासिल करेंगे :

- 30 लाख लोगों (इनमें से 21 लाख महिलाओं) को ऋण, बीमा एवं बचत तक पहुंच प्रदान करने और उन्हें गरीबी से उबरने में मदद करेंगे।
- नर्सों, दाईयों या डॉक्टरों की मदद से लगभग 4,00,000 माताओं को अधिक सुरक्षित ढंग से प्रसूति में मदद करेंगे।
- पोषण कार्यक्रमों के लाभ 39 लाख बच्चों तक पहुंचाएंगे।
- 58 लाख लोगों को स्वच्छता की बेहतर सुविधाएं देंगे।
- निम्न कार्बन ऊर्जा के साथ 39 लाख लोगों को जलवायु परिवर्तन से संघर्ष करने में मदद करेंगे (जैसे- ईंधन-कुशल स्टोव और सौर ऊर्जा-चालित लालटेन)।
- 8,00,000 बच्चों को सेकन्डरी स्कूल और 15 लाख बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में पंजीकरण कराने में सहायता करेंगे।
- 1.60 करोड़ अधिक लोगों (इनमें से 93 लाख महिलाओं) को अपने अधिकारों एवं हकदारियों को समझने और उन पर दावा करने में मदद करेंगे।



विकास के लिए व्यापार: गरीब लोगों के पास नौकरियों या आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए अक्सर निपुणताएं एवं वित्तीय प्रबंध (फाइनेंस) नहीं होते। हमारे नए निजी सेक्टर कार्यक्रम निम्न आय वाले राज्यों में गरीब लोगों, खासकर महिलाओं को नौकरियों, निपुणताओं के लाभ दिलाने और वित्तीय प्रबंध तक उनकी पहुंच कायम करने में मदद करेंगे। हम महिलाओं को उनकी आय में वृद्धि, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार और उनके घरेलू वित्तीय प्रबंधन एवं व्यावसायिक उपक्रम को बेहतर ढंग से चलाने में मदद करेंगे।

हम किनके साथ मिल-जुलकर कार्य करेंगे

डीएफआईडी भारत सरकार, राज्य सरकारों और अधिकाधिक रूप से निजी सेक्टर, सामाजिक संगठनों, थिंक टैंक्स अन्य दानदाताओं की साझेदारी के साथ भारत में अपने कार्यक्रमों पर अमल करता है। हम ब्रिटेन सरकार के विभागों के साथ मिल-जुलकर भी व्यापार, जलवायु परिवर्तन, ढांचागत सुविधाओं, शोध, शिक्षा और निपुणताओं के बारे में व्यापक प्राथमिकताओं में योगदान देते हैं।

हम किस प्रकार कार्य करेंगे

हमारा पहले की अपेक्षा अधिक कर्तव्य यह दर्शाने का है कि हमारे द्वारा विकास पर खर्च किए गए प्रत्येक पाउंड का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। नतीजतन, पारदर्शिता और जवाबदेही हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के साथ उसकी गरीबी में कमी आएगी और भारत विश्व मामलों में अधिक प्रमुख देश बनेगा। इस दौरान भारत के साथ विशेषज्ञता साझा करने, नव-प्रवर्तन को समर्थन देने और निपुणताओं के निर्माण में हमारी साझेदारी अधिक होगी। अगले चार सालों में हम निम्नलिखित कार्यों पर जोर देंगे।

- **भारत के निम्न आय वाले राज्यों में अति-गरीब लोगों पर ध्यान केंद्रित करना :** ब्रिटिश सहायता से तीन गरीब राज्यों- मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में अति-गरीब लोगों को लाभ पहुंचेंगे। पिछले दशक के दौरान गहन, लाभकारी साझेदारियों को आगे बढ़ाने के जरिए यह कार्य किया जाएगा।
- **हमारे कार्य में महिलाओं और लड़कियों को केंद्र-बिंदु बनाना :** ब्रिटेन इन क्षेत्रों में निवेश करेगा : लड़कियों की शिक्षा, फाइनेंस, निपुणताओं और निम्न कार्बन तक पहुंच, सुरक्षित प्रसूति, पसंद के आधार पर बच्चों को जन्म, महिलाओं पर हिंसा में कमी लाना, बाल स्वास्थ्य एवं पोषण और स्वच्छता।
- **गरीबी उन्मूलन में निजी सेक्टर की क्षमता का संवर्द्धन :** निम्न आय वाले राज्यों में विकास को समर्थन देने के लिए ब्रिटेन भारतीय संस्थाओं के साथ मिल-जुलकर गरीबोन्मुख निजी निवेश के कार्यक्रम विकसित करेगा। ये कार्यक्रम उन लघु एवं मझोले उद्यमों, कृषि व्यापार, ऊर्जा, ढांचागत सुविधाओं एवं वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में होंगे, जिनसे निम्न आय वाले राज्यों में गरीब लोगों को सीधा लाभ पहुंचता हो।
- **उन वैश्विक मसलों के बारे में भारत के साथ प्रगाढ़ सहयोग कायम करना, जिनसे अन्य जगहों के गरीब लोगों को लाभ मिल सकते हों :** जैसे विकास एवं व्यापार, जलवायु परिवर्तन, संसाधनों का अभाव और स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण।

अधिक जानकारी के लिए:

भारत की कार्यशील योजना के बारे में विस्तृत विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें- www.dfid.gov.uk/india

या संपर्क करें : डीएफआईडी इंडिया, बी-28, तारा क्रेसेन्ट, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016

क्राउन कॉपीराइट 2011. सज्जा संबंधी कार्य और डिजाइन का कॉपीराइट क्राउन के पास है। यह प्रकाशन (लोगो को छोड़कर) किसी भी फॉर्मेट या माध्यम में पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते इसे सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए और भ्रामक संदर्भ में इस्तेमाल न हो। निर्दिष्ट प्रकाशन के शीर्षक और स्रोत के साथ क्राउन कॉपीराइट के रूप में आभार प्रकट करते हुए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। डिपार्टमेंट फोर इंटरनेशनल डेवलपमेंट 2011 द्वारा प्रकाशित।